

वशिव व्यापार संगठन पैनल का भारत के खिलाफ फैसला

प्रलिस के लयि:

वशिव व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ, संरक्षणवाद, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता

मेन्स के लयि:

वशिव व्यापार संगठन का भारत के खिलाफ फैसला

चरचा में क्यों?

हाल ही में वशिव व्यापार संगठन पैनल ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क संबंधी ववाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है।

प्रमुख बदि

पृष्ठभूमि:

- भारत का लक्ष्य घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी वनिरमाण को बढ़ावा देना और आयात पर अपनी नरिभरता को कम करना रहा है, लेकनि यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा इस दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है जनिका तरक है कएसे उपाय संरक्षणवादी हैं तथा वैश्वकि व्यापार नयिमें का उल्लंघन करते हैं।
- वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ ने एकीकृत सर्कटि, मोबाइल फोन और घटकों सहति वभिनिना T उत्पादों पर 7.5% से 20% तक आयात कर लगाने के भारत के फैसले को चुनौती दी तथा दावा कयि कयिे दरें अनुमत सीमा से अधिक हैं।
- जापान और ताइवान द्वारा भी यही शकियायत की गई है।

आदेश/नरिणय:

- पैनल का मानना था कभारत द्वारा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाया गया सीमा शुल्क वैश्वकि व्यापार नयिमें का उल्लंघन है, इसका मुख्य कारण उन उत्पादों का सूचना प्रौद्योगिकी समझौते की शर्तों के साथ असंगत होना माना गया है।
 - ITA एक वैश्वकि व्यापार समझौता है जसिका उद्देश्य IT उत्पादों की एक वसितुत शृंखला पर सीमा शुल्क को समाप्त करना है। भारत वर्ष 1996 के वैश्वकि व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- इस फैसले ने वैश्वकि मानदंडों और दायतित्वों के साथ अपनी व्यापार नीतयिों को संरेखति करने के लयि भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- यह उन चुनौतयिों को भी रेखांकति करता है जनिका सामना भारत जैसे वकिसशील देशों को अंतर्राष्टीय व्यापार प्रतबिद्धताओं के साथ अपनी घरेलू नीतयि में संतुलन हेतु करना पड़ता है।

भारत का तरक:

- भारत ने तरक दयिा कभारत पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे और इसलयि यह ऐसी वसतुओं पर टैरफि को समाप्त करने के लयि बाध्य नहीं है।

आशय:

- यूरोपीय आयोग के अनुसार, यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारकि भागीदार है, जसिका इसिसा वर्ष 2021 में कुल भारतीय व्यापार का 10.8 प्रतशित था।
- भारत के खिलाफ WTO के नरिणय का भारत और यूरोपीय संघ के साथ-साथ जापान तथा ताइवान के बीच व्यापार संबंधों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा प्रस्तुत चुनौती के चलते भारत को आयात शुल्क कम करना या समाप्त करना पड़ सकता है। इसका भारत के घरेलू वनिरमाण क्षेतर पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, जसिे इस प्रकार के टैरफि द्वारा संरक्षणति कयिा गया है।

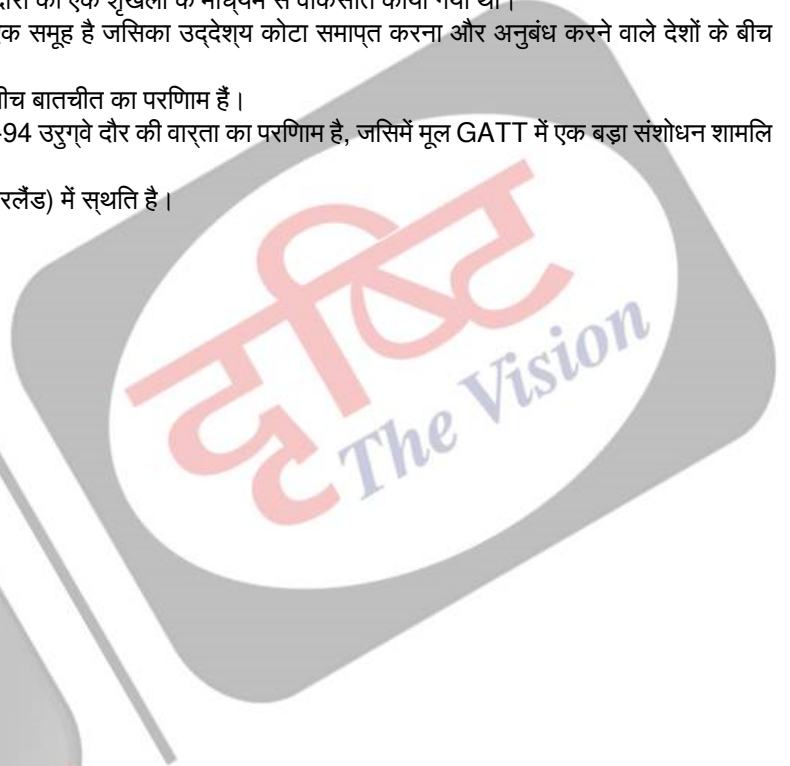
वशिव व्यापार संगठन के नरिणय के बाद भारत के पास वकिल्प:

- भारत के पास IT टैरिफ पर WTO के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है, लेकिन यदि भारत अपील करता है तो मामला कानूनी उत्पीड़न के तहत माना जाएगा।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि WTO की शीर्ष **अपीलीय पीठ** न्यायाधीश नयुक्तियों के अमेरिकी वरिष्ठ के कारण **अब कार्य नहीं कर रही है**।
 - कानूनी शोधन (Legal Purgatory) का उपयोग ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिये किया जाता है जहाँ एक कानूनी मामला या विवाद बना समाधान या स्पष्ट मार्ग के कारण **अधर में लटका हो**।
 - यह स्थिति उन देशों के लिये विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो व्यापार विवादों को पारदर्शी और नयिम-आधारित तरीके से हल करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह **वशिव व्यापार संगठन के विवाद नपिटान तंत्र की प्रभावशीलता को कम करता है**।

वशिव व्यापार संगठन (WTO):

परचिय:

- यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। वशिव व्यापार संगठन **द्वितीय वशिव युद्ध** के मद्देनजर स्थापित **टैरिफ और व्यापार (GATT)** पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है।
 - इसका उद्देश्य संभावित व्यापार प्रवाह को सुचारु, स्वतंत्र बनाने में मदद करना है।
 - इसमें 164 सदस्य शामिल हैं और वशिव व्यापार इनकी 98% की हस्सेदारी है।
- इसे GATT के तहत आयोजित व्यापार वार्ताओं या दौरों की एक शृंखला के माध्यम से वकिसति किया गया था।
 - GATT बहुपक्षीय व्यापार समझौते का एक समूह है जिसका उद्देश्य कोटा समाप्त करना और अनुबंध करने वाले देशों के बीच टैरिफ शुल्क में कमी करना है।
- वशिव व्यापार संगठन के नयिम-समझौते सदस्यों के बीच बातचीत का परणाम हैं।
 - वर्तमान स्वरूप काफी हद तक वर्ष 1986-94 उरुग्वे दौर की वार्ता का परणाम है, जिसमें मूल GATT में एक बड़ा संशोधन शामिल था।
- वशिव व्यापार संगठन का सचवालय जनिवा (स्वटिज़रलैंड) में स्थित है।



वशिव व्यापार संगठन मंत्रसितरीय सम्मेलन:

- यह वशिव व्यापार संगठन का शीर्ष नरिणय लेने वाला नकिय है और आमतौर पर हर दो साल में इसकी बैठक होती है।
- वशिव व्यापार संगठन के सभी सदस्य मंत्रसितरीय सम्मेलन में शामिल होते हैं और वे कसि भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आने वाले सभी मामलों पर नरिणय ले सकते हैं।

चतिाएँ:

- न्यायाधीश नयुक्तियों को लेकर अमेरिकी वरिष्ठ के कारण **WTO** के शीर्ष अपीलीय अधिकारी अब काम नहीं कर रहे हैं।
- वर्तमान स्थिति उन चुनौतियों को उजागर करती है जनिका सामना वशिव व्यापार संगठन को वर्तमान वैश्विक संदर्भ में व्यापार विवादों को हल करने में करना पड़ता है, **देश संरक्षणवादी उपायों को तेज़ी से अपना रहे हैं** जो नयिम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को चुनौती दे रहे हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुगम बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।

2. TFA, WTO के बाली मंत्रसितरीय पैकेज 2013 का एक भाग है ।
3. TFA, जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- वर्ष 2013 के बाली मंत्रसितरीय सम्मेलन में व्यापार सुवधि समझौते (Trade Facilitation Agreement- TFA) पर बातचीत की गई थी । अतः कथन 2 सही है ।
- यह विश्व व्यापार संगठन के दो-तर्हिई सदस्यों के अनुसमर्थन के बाद 22 फरवरी, 2017 को लागू हुआ । अतः कथन 3 सही नहीं है ।
- भारत ने 2016 में TFA की पुष्टि की थी । अतः कथन 1 सही है ।
- TFA के तहत पारगमन में वस्तु की आवाजाही, नपिटान और नकिसी में तेज़ी लाने के प्रावधान शामिल हैं । यह व्यापार सुवधि एवं सीमा शुल्क व अन्य उपयुक्त अधिकारियों के बीच प्रभावी सहयोग हेतु उपायों को भी नरिधारति करता है
- अनुपालन के मुद्दे: इसमें भवषिय में इस क्षेत्र में तकनीकी सहायता और क्षमता नरिमाण हेतु प्रावधान शामिल हैं ।
- अतः विकल्प (a) सही है ।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wto-panel-rules-against-india>

